E-ISSN: 2583-9667
Indexed Journal
Peer Reviewed Journal
https://multiresearchjournal.theviews.in

Received: 22-10-2025
Accepted: 27-12-2025
Published: 29-01-2026

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY

Volume 4; Issue 1; 2026; Page No. 228-230

विमुद्रीकरण एवं देश के आर्थिक विकास

कृष्णा कुमारी

शोधार्थी, स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग, तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार, भारत

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20051954

Corresponding Author: कृष्णा कुमारी

सारांश

विमुद्रीकरण के मूल्याकन अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि विमुद्रीकरण ने भारत की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से ही नही अपितु नकारात्मक रूप से भी प्रभावित किया है भारत में कुल जनसंख्या के लगभग 70 फीसदी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। अतः यह कहना उचित होगा कि शहरी क्षेत्रो की अपेक्षा ग्रामीण परिवेश विमुद्रीकरण से अत्यधिक प्रभावित हुआ है । चुकीं विमुद्रीकरण नगदी से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, अतः कहा जा सकता है कि ग्रामीण परिवेश में अर्थिक क्षेत्र के साथ– साथ सास्कृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। क्योकि ग्रामीण लोग अधिकांश कार्य नगद में करते है। विमुद्रीकरण से देश में ग्रामीण मजदूर वर्ग के रोजगार विहिन रहने, छोटे छोटे व्यवसायो के ठप होने तथा सामाजिक कार्यक्रमों के बाधित होने जैसे कई प्रभाव हुए है। विमुद्रीकरण का निर्णय सरकार सरकार की एक सकारात्मक सोच का प्रदर्शन करता है परन्तु इसके साथ साथ सरकार को नोटो की मांग के अनुसार पूर्ति, कमजोर व सीमित बैकिंग ढाचें को दूरस्त करना तथा बैकों में कार्यस्थल पर भ्रष्टाचार को रोकना आदि उपाय साथ साथ में किए जाने चाहिए थे। साथ ही ग्रामीण लोगो के लिए विशेषतः किसानो को फसलो की बिक्री पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस भी दिए जाने, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत वितरित ऋण पर ब्याज वसूली में छूट दिए जाने, मनरेगा के कार्य दिवसो में वृद्धि करने तथा सम्भावित अतिरिक्त कर सग्रंह से सामाजिक कल्याण की नई योजना शुरू करने जैसे उपाय भी करना आवश्यक है जिससे कि विमुद्रीकरण से होने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सकता अथवा समाप्त किया जा सकता है विमुद्रीकरण अर्थव्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता, कालाधन की समाप्ति, आतकंवाद पर रोक तथा जाली नोटो को निष्क्रिय करने की सरकार की एक अनुठी पहल है।

मूल शब्दः सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था, सकारात्मक, नकारात्मक, ग्रामीण परिवेश, सामाजिक कल्याण, पारदर्शिता, कालाधन

प्रस्तावना

विमुद्रीकरण से देश के आर्थिक विकास की रफ्तार और तेजी से बढने की उम्मीद से किया कदम है। 500–1000 रू के नोटो पर पाबंदी के बाद अर्थव्यवस्था के लूप होल्स (मसलन कालाधन, नकली नोट और शैडो बैकिंग आदि) भरेगे जिससे देश की अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। विमुद्रीकरण के उद्देश्य की बात करें तो वो इस प्रकार है–

1. यह अघोषित सच है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी खर्च की जाती है। चाहे टिकट खरीदने की बात हो, मतदाताओं को बाटने की बात हो या फिर प्रचार व अन्य लेनदेन। यह फैसला तबके यू.पी., पंजाब गुजरात, गोवा, उत्तराखण्ड जैसे राज्यो में विद्यानसभा चुनाव पर प्रभाव डाला है। ऐसे नेता जिन्हाने इन चुनावो के लिए ब्लैक मनी जमा की होगी वो उसका इस्तेमाल नही कर पाएंगे। ऐसे में चुनाव अपेक्षाकृत ज्यादा पारदर्शी होगे की संभावना ज्यादा दिखा।
2. गैर निष्पादित परिसंपतियों के उच्चतम स्तर और ऋण देने हेतु अनुपलब्ध धनराशी की गंभीर समस्या झेल रहे बैकिंग क्षेत्र को बडी मात्रा में नकदी प्राप्त हुई जिससे उनकी मौद्रिक तरलता में वृद्धि हुई । बैंको की मोद्रिक तरलता में हुई यह अभुतपूर्व वृद्धि अर्थव्यवस्था को कई तरीको से लाभावित्त हुई।
3. इसका पहला बड़ा प्रभाव यह होगा कि बैंको द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की दरों में कमी आयी।
4. बैकों में बढ़ी हुई तरलता एवं घटी हुई ब्याज दरो के कारण नविन योजनाओं को गति मिली तथा निवेश बढा ।
5. विमुद्रीकरण द्वारा बाजार में नकदी के अभाव के कारण मांग में कमी दर्ज की गई जिससे महंगाई में कमी आई। दिसम्बर 2016 में खुदरा महगाई दर घटकर 3.41 फीसदी पर आ गई।
6. विमुद्रीकरण से सरकार के राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । वितमंत्रालय के आकडो के अनुसार दिसम्बर 2016 महिने में उत्पाद शुल्क में 31.6 फीसदी और सेवा कर संग्रह में 12.4 फीसदी वृद्धि हुई है। बढा हुआ राजस्व संग्रह निस्संदेह सरकार के वित प्रबंधन को लाभ पहुचाया।

7. इससे वितीय क्षेत्र में डिजिटल लेनदेन को बढावा मिला। उपभोक्ताओं में डेबिटकार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई–वॉलेट जैसे भूगतान माध्यमों द्वारा भुगतान करने की प्रवृति में इजाफा हुआ। बढती हुई डिजिटल लेनदेन की प्रवृति वित्तीय तंत्र में पारदर्शिता लाएगी। साथ ही यह लोगो को कैश लेकर चलने में होने वाली असुविधा से मुक्ति दिलाई तथा केशलैस हस्तांतरण के द्वारा सभी हस्तातरण कर्त्ताओं को कर के दायरे में लाने का प्रयास किया गया है।
8. आर. बी. आई. के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव के अनुसार "विमुद्रीकरण अपने अन्य लाभों के साथ–साथ निवेश में वृद्धि के लिए सकारात्मक माहौल पैदा किया, अपने परिणामों में यह महगाई में कमी लाया और महान कैश अर्थव्यवस्था की और ले जारहा है।
9. रू 500–1000 पर पाबंदी लगाने से बैकं की दरे घटेगी जिससे की फ्लैट तथा जमीनो की कीमते कम होगी परिणामस्वरूप अपने घर का सपना देखने वाले लोगो के वाकई अच्छे दिन आएगे।
10. नोट बदलने से नकली नाटो की समस्या पर लगाम लगी है क्योकी नए नोटो की सीरिज में सिक्योरिटी फीचर ज्यादा है। जिनकी नकल करना किसी व्यक्ति अथवा दूसरे देश के लिए बेहद मुश्किल होगा।
11. विमुद्रीकरण से आतकंवाद, उग्रवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद मे कमी आई है। रू 500–1000 के नोटो पर पांबदी से आतकंवाद के वित्तीय स्त्रोत पर भी चोट लगी है। नकली नोट रद्दी हो गए। अवैध रूप से जमा कैश बेकार हो गया तथा आतकी सगंठनो में अवैध रूप से प्रयुक्त हो रही भारतीय मुद्रा पर लगाम लगी है। हाल ही में आतकवादी उग्रवादी और नक्सलवादी घटनाओं में आई कमी इस मत को पुष्ट भी करती है।

विमुद्रीकरण के नुकसान :– इसमें कोई दो राय नही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विमुद्रीकरण के कई सकारात्मक परिणाम सामने आए परन्तु सरकार की ओर से एका एक अमल में लाई गई विमुद्रीकरण की इस प्रक्रिया ने संपूर्ण भारतीय आर्थिक परिदृ ष्य को आमूल चूल रूप से प्रभावित भी किया। विमुद्रीकरण के इस कदम से कई नकारात्मक परिणाम भी सामने आए जो कि निम्न प्रकार है।

- विमुद्रीकरण के कारण अर्थव्यवस्था में नकदी का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। एक अनुमान के मुताबिक विमुद्रीकरण से पूर्व जितनी करेंसी प्रचलन में थी उसमें 500 और 1000 रूपये के नोटो का हिस्सा लगभग 86 प्रतिशत था । ऐसे में एकाएक इन नोटो का प्रचलन रोक देने से नकद की कठिनाइयां आई। आर.बी.आई द्वारा नए नोटो की मांग से कम निर्गमन, कमजोर व सीमित बैकिंग ढांचा और बैंक के कुछ अधिकारियों व कर्मचारियो द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के कारण नकदी का संकट विकराल होता चला गया।
- विमुद्रीकरण ने श्रम, भूमि व कर संबंधी आर्थिक सुधारो को अधर में लटका दिया क्योकि सरकार के लिए भी यह मुमकिन नही है कि वह एक साथ कई आर्थिक सुधारो के गति दे सके। तात्कालिक नकारात्मक प्रभाव जीएसटी का अधर में लटकना है । क्योकि यह 1 अप्रैल 2017 को प्रस्तावित होना था जो कि अब सम्भवतः जुलाई में होगा।
- विमुद्रीकरण से उत्पादन, खपत और निवेश में कमी आई है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलु उत्पाद का महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें कृषि, विनिमार्ण, सेवा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2016 में भारत का सकल घरेलु उत्पाद लगभग 2300 अरब डालर था तथा भारत सरकार द्वारा 2016–17 में 7.6 प्रतिशत सकल घरेलु उत्पाद प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया जो कि सम्भवतः विमुद्रीकरण के कारण 7.1 प्रतिशत तक ही प्राप्त हो सकेगा।

विमुद्रीकरण का ग्रामीण विकास पर प्रभाव

- एसोचौम के अनुसार नोटबदी का सबसे बुरा प्रभाव सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योगो पर पडा है। नोटबदी को बिना पुख्ता इंतजाम के किया जाना बहुत परेशानियों को जन्म दे रहा है। नोट बन्दी का सबसे ज्यादा नुकसान छोटी फर्मों को हुआ है, क्योकि ये नगद में व्यवहार करती है।
- देश की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे महत्पूर्ण स्थान हैं। देश मे कुल रोजगार का 70 फीसदी रोजगार गांवो में है। देश के सकल घरेलु उत्पाद का 50 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता है। इससे जाहिर है, कि 8 नवम्बर 2016 को प्रधान मंत्री के फैसले का सर्वाधिक प्रभाव ग्रामीण भारत पर हुआ। जब देश में नोटबदी का फैसला आया तो देश के किसानो के सामने रबी फसल की बुआई की बडी चुनौती थी जिन राज्यों में रबी बुआई की बडी चनौती थी। इस परिस्थिति ने कृषको के सम्मुख बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि की अनुपलब्धता की समस्या उत्पन्न कर दी जिससे अधिकांश किसानो को पुराने पडे बीज से बुआई करनी पडी । परिणामस्वरूप कैश न होने के कारण उन्हे बाजार सुधरने का इतंजार करना पडा जिससे रबी की फसल बुआई में देरी हुई।
- ग्रामीण इलाकों में रोजगार के लिए केन्द्रीय स्कीम मनरेगा बुरी तरह प्रभावित हुई है । क्योकि नोटबंदी लागू होने के बाद से सरकार श्रमिको को यथा समय भुगतान करने में असमर्थ हुई।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र का हिस्सा 90 प्रतिशत से अधिक है। जिसमें कार्यरत कामगार वर्ग अपनी मजदूरी या वेतन नकदी में प्राप्त करता है। ऐसे में एकाएक उपजे नगदी संकट ने इन्हे अत्यधिक प्रभावित किया इसका प्रभाव इस स्तर तक देखा गया कि महानगरो व उनके उपनगरीय तथा बडे शहरो में रेड्डी दृ पटरी वाले, छोटे मोटे व्यापार करने वाले तथा दैनिक मजदूर अपने गावं लोटने को विवश हो गए।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बडा प्रभाव रिवर्स माइग्रेशन का दिखाई दिया। शहरो में रियल एस्टेट सेक्टर और उद्योगो में श्रमिको को भुगतान में दिक्कतो के चलते लोग गांव का रूख करने पर मजबूर हो गए। नोटबंदी लागू होने के बाद

से गांव पलायन कर चुके श्रमिको को देश में एक बार फिर कैश की किल्लत खत्म होने का इतजार है।

- नोटबदी के दौर में सबसे बडी समस्या ग्रामीण क्षेत्रो में पुराने नोट जमा कराने तथा नये नोट निकालने में हुई। देश की कुल जनसख्या का लगभग 70 फीसदी गांवो में रहता है लेकिन उन्हे महज कुल एटीएम मशिनो का 45 प्रतिशत ही उपलब्ध है तथा एटीएम से पैसै निकालने के लिए उन्हें 5 से 25 किमी की यात्रा करनी होती है। इसके बावजूद 8 नवम्बर 2016 के बाद ग्रामीण इलाको में एटीएम और बैंक तक पैसा पहुचाने में सबसे ज्यादा समय लगा ।
- नोटबदी से पहले भी देश में कालेधन छिपाने के लिए ग्रामीण इलाको में खेती की जमीन के खरीद फरोख्त का मायाजाल चलता था नोटबदी लागू होने के बाद एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में जनधन खातो का गलत इस्तेमाल करते हुए कालेधन को छिपाने की भरपुर कोशिश की गई।

विमुद्रीकरण के मूल्याकन अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि विमुद्रीकरण ने भारत की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से ही नही अपितु नकारात्मक रूप से भी प्रभावित किया है भारत में कुल जनसंख्या के लगभग 70 फीसदी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। अतः यह कहना उचित होगा कि शहरी क्षेत्रो की अपेक्षा ग्रामीण परिवेश विमुद्रीकरण से अत्यधिक प्रभावित हुआ है । चुकीं विमुद्रीकरण नगदी से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, अतः कहा जा सकता है कि ग्रामीण परिवेश में अर्थिक क्षेत्र के साथ–साथ सास्कृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। क्योकि ग्रामीण लोग अधिकांश कार्य नगद में करते है। विमुद्रीकरण से देश में ग्रामीण मजदूर वर्ग के रोजगार विहिन रहने, छोटे छोटे व्यवसायो के ठप होने तथा सामाजिक कार्यक्रमों के बाधित होने जैसे कई प्रभाव हुए है।

विमुद्रीकरण का निर्णय सरकार सरकार की एक सकारात्मक सोच का प्रदर्शन करता है परन्तु इसके साथ साथ सरकार को नोटो की मांग के अनुसार पूर्ति, कमजोर व सीमित बैकिंग ढाचें को दूरस्त करना तथा बैकों में कार्यस्थल पर भ्रष्टाचार को रोकना आदि उपाय साथ साथ में किए जाने चाहिए थे। साथ ही ग्रामीण लोगो के लिए विशेषतः किसानो को फसलो की बिक्री पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस भी दिए जाने,किसान क्रेडिट कार्ड के तहत वितरित ऋण पर ब्याज वसूली में छूट दिए जाने, मनरेगा के कार्य दिवसो में वृद्धि करने तथा सम्भावित अतिरिक्त कर सग्रंह से सामाजिक कल्याण की नई योजना शुरू करने जैसे उपाय भी करना आवश्यक है जिससे कि विमुद्रीकरण से होने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सकता अथवा समाप्त किया जा सकता है विमुद्रीकरण अर्थव्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता, कालाधन की समाप्ति, आतकंवाद पर रोक तथा जाली नोटो को निष्क्रिय करने की सरकार की एक अनुठी पहल है।

निष्कर्ष

विमुद्रीकरण द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया है, जिससे की लोगो को नगद साथ लेकर चलने वाली कठिनाईयो से मुक्ति मिल सके तथा वित्तीय तंत्र में पारदर्शिता हो। वितिय क्षेत्र में डिजिटल लेनदेन को बढावा देना भी विमुद्रीकरण का एक अहम उद्देश्य रहा है। साथ ही कालाधन आतकंवाद तथा जाली नोटो पर रोक भी इसके मुख्य उद्देश्य हैं चूंकि भारत की अधिकाश जनसंख्या गांवो में निवास करती है। विकास मुख्यत विमुद्रीकरण से प्रभावित हुआ है। ये प्रभाव सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनो ही रूप में पड़ा है। लेकिन इसे सही रूप में माप पाना कठिन कार्य है।

संदर्भ

1. आर्थिक समीक्षा (भारत सरकार) 2016 – 17
2. दृष्टि (द विजन), करेंट अफेयर्स टुडे, मार्च 2017, अंक 10
3. समाचार पत्र, द हिन्दु, इडियन एक्सप्रेस, टाइम्स आफ इण्डिया, इकानॉमी टाइम्स, जन शक्ति, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका ।
4. डां. कविता राव, डां. सुधाशु कुमार एवं अन्य, षडिमोनेटाइजेशनः इम्पेक्ट ऑन द इकोनॉमी, एन. पी. एफ. पी., पेपर नम्बर 182, नई दिल्ली, 2016
5. इकॉनोमिक एण्ड पॉलिटीकल वीकली, 2016
6. अरिधमं चन्दा, नोट्स ऑन डीमोनेटाइजेशन, दिसम्बर 2016
7. पी.टी. आई. (2016). डिमोनेटाइजेशन विल बेनिफिट्स इकोनोमी इन लोग रनं ।

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.